











# भारत में निवेश

## सराहनीय कदम

अमेरिकी निजी निवेश फर्म जनरल एटलांटिक ने भारत में अपना वार्षिक निवेश चार गुना करने का निर्णय किया है। विकास-इक्विटी निवेशक 'जनरल एटलांटिक' ने घोषणा की है कि वह भारत में अगले कुछ वर्ष तक 1 बिलियन डालर तक का नया निवेश करेगी। यह भारतीय अर्थिक नीति की उल्लेखनीय सफलता है। जनरल एटलांटिक के प्रबंध निदेशक तथा भारतीय शाखा के प्रमुख शांतनु रस्तोगी ने एक खबरिया एजेंसी को बताया, 'हमारी नजर सरकार द्वारा किए गए बड़े नीतिगत परिवर्तनों पर है जिससे सेवाओं व सेवुओं में डिजिटल ढांचागत संरचना बनाने को बढ़ावा मिलेगा। वित्तीय समावेशन के लिए सस्ती सप्लाई व सस्ती ढांचागत संरचना तथा सस्ता डेटा हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं।' न्यूयार्क की इक्विटी फर्म वैश्विक स्तर पर लगभग 71 बिलियन डालर परिसंपत्तियों का प्रबंधन करती है और उसने पिछले दो दशक से अधिक समय में भारत में 4.6 बिलियन डालर का निवेश किया है। प्रति वर्ष औसतन 230 डालर से प्रति वर्ष 1 बिलियन डालर का निवेश लंबी छलांग होगा। जनरल एटलांटिक ने भारत में वालमार्ट-स्वामित्व वाले डिजिटल भुगतान एन-फोनपे प्राइवेट-पीई का समर्थन किया है। पीई ईडिया की कार्रवाइयों का विकास नियांतोन्युख सेवायें प्रदान करने वाली फर्मों को प्रोत्साहन देने की दिशा में हुआ है। वे भारत में बढ़ते घरेलू उपभोग को लक्ष्य बनाती हैं। इसके केन्द्रित क्षेत्रों में उद्यमिता सोसाइटी, स्वस्थरक्षा व वित्तीय सेवा कंपनियां हैं। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश-एफडीआई में कमी की पृष्ठभूमि में जनरल एटलांटिक की



आलोचना की है। उनका कहना है कि सरकार इसमें सक्षम नहीं है। लोक वास्तव में यह स्थिति समझ से परे है। वर्तमान सरकार राजकोट अनुशासन के प्रति पूर्णतः प्रतिबद्ध है। यहां तक कि कोविड वैश्विक महामारी के कारण आई विकलांगकारी बाधाओं वाले समय में भी इस राजकोषीय व्यावहारिकता बनाए रखी है। सरकार ने पूंजीगत खर्च बढ़ाव दिया है तथा अनेक अर्थीक सुधार किए हैं। इसके बावजूद एफडीआई आकाश न होने का कारण संभवतः मोदी सरकार द्वारा अपने पहले कार्यकाल पर उदारीकरण के आयाम व स्तर के बजाय कल्याणकारी उपायों पर ज्ञान ध्यान देना रहा है। सरकार को एयर इंडिया का निजीकरण करने में साल का समय लगा, जबकि एक सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम-पीएसयू के पार यह सुधार योग्य नहीं रह गई थी। हालांकि, पिछले कुछ साल में सरकार ने आर्थिक सुधार तेज करने के प्रयास किए हैं जिसकी सर्वाधिक साधन प्रतिक्रिया निजीकरण के क्षेत्र में दिखती है। सरकार ने केवल एयर इंडिया बेची है, बल्कि वह बीपीसीएल व शिपिंग कार्पोरेशन जैसे बड़े पीएसयू बाहर निकलने का प्रयास कर रही है। लेकिन मुख्यतः खरीदारों की वाले के कारण वह इसमें पूर्णतः सफल नहीं हुई है। मोदी नीति सरकार सराहना की जानी चाहिए कि वह कभी अनेक लोगों की हानिकारक साधन की शिकार नहीं बनी। इसमें कुछ अर्थशास्त्री भी शामिल थे जो किसे किसी बहाने अनाप-शनाप खर्च की पैरवी करते थे। इसके साथ ही भारत ने ढांचागत निर्माण पर भारी खर्च किया है। इससे वैश्विक बिजनेस प्रभाव हुए हैं तथा निवेशक और फाइनेंसर भारत को पैसा लगाने का अच्छा समानने लगे हैं। भारत में एपल की बढ़ती दिलचस्पी तथा जनरल एटलार्ड की हालिया घोषणा देश में निवेश की दिशा में सराहनीय कदम हैं।

# विकास को कर्नाटक का आशीर्वाद

सुमित भसीन  
(लेखक, राजनीति  
विश्लेषक हैं।)



**क** नार्टक की जनता 10 मई को अपने भविष्य का फैसला कर रही है। मतदाताओं को अगली पीढ़ी के लिए निर्णय का अधिकार मिला है। आगले कुछ साल में कर्नाटक 1 ट्रिलियन डालर की अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है। भारत जल्द ही दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है जिसमें कर्नाटक के विकास इंजन का महत्वपूर्ण योगदान होगा। इस प्रकार कर्नाटक का विधानसभा चुनाव मतदाताओं पर भारी जिम्मेदारी डालता है कि वे अपना निर्णय सोच-समझ कर लें। मतदाताओं के समक्ष विकल्प स्पष्ट है। उनको अर्थिक विकास तथा 'ख़ेरातों' की राजनीति के बीच चयन करना है। कर्नाटक के संसाधन कर्नाटक के विकास, सामूहिक बेंजरी तथा जनता व भावी पीढ़ियों की समुद्दिश का साधन बन सकते हैं। इसके उलट दूसरी स्थिति में कर्नाटक के संसाधन 'ख़ेरातों' के वित्त-पोषण में खर्च होकर राज्य के सामने बाधायें खड़ी करने व विकास के इंजन को पटरी से उतारने का काम कर सकते हैं। समाज के सभी वर्गों तक पहुंचने वाली समावेशी वृद्धि के अर्थिक माडल तथा ख़ेरातों की राजनीति के बीच मुकाबला है जो एक प्रकार के 'गरीबवाद' को बढ़ावा दे सकती है। कर्नाटक भारत के प्रगतिशील राज्यों में शामिल है। कर्नाटक ऐसा राज्य भी है जहां नौजवान अपने सपने पूरे कर रहे हैं। कर्नाटक भारत की स्टार्टअप राजधानी भी है। यहां प्रत्यक्ष विदेशी निवेश-एफडीआई 2019 में 311 मिलियन डालर से बढ़ कर 2020-21 में 1.34 बिलियन डालर पहुंच गया है। 2019-20 और 2021-22 के बीच कुल एफडीआई में कर्नाटक का हिस्सा सर्वोच्च पांच राज्यों में शामिल था जो 2019-20 में 22.43 प्रतिशत से बढ़ कर 2021-22 में 49.40 प्रतिशत पहुंच गया। राज्य ने 2022-23 में भी अपनी महत्वपूर्ण स्थिति बनाए रखी है।

---

For more information about the study, please contact Dr. John Smith at (555) 123-4567 or via email at [john.smith@researchinstitute.org](mailto:john.smith@researchinstitute.org).

An aerial photograph of the newly built terminal at the airport. The terminal features a large, white, fan-shaped roof with a central entrance. It is surrounded by a modern parking area and a road network. In the background, there are several green fields and some smaller buildings.

बिलियन डालर तथा 2030 तक 1 ट्रिलियन डालर तक पहुंचा सकता है। कर्नाटक जल्द ही राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का दसवां हिस्सा बन सकता है। कर्नाटक की प्रति व्यक्ति आय भी तेजी से बढ़ रही है। पिछले दशक में राज्य में रिकार्ड 208.86 प्रतिशत वृद्धि हुई, जबकि राष्ट्रीय औसत 136.87 प्रतिशत था। कर्नाटक की प्रति व्यक्ति जीएसडीपी 3.32 लाख रुपये है। कर्नाटक की असाधारण अर्थिक वृद्धि ने सबके जीवन को प्रभावित किया है। कर्नाटक के संसाधन छोटी एवं लघु सिंचाई सुविधाओं के विस्तार तथा घरों में पेयजल की पहुंच बढ़ाने पर खर्च किए जा रहे हैं जिनमें राज्य के ग्रामीण क्षेत्र भी शामिल हैं।

राज्य सरकार की 'विद्यानिधि' योजना में किसानों, भूमिहीन मजदूरों तथा बुनकरों के बच्चों व गरीब महिलाओं को स्कालरशिप दी जाती है ताकि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुंच बना कर वे अपना भाग्य स्वयं लिख सकें। वित्त वर्ष 2022 में कर्नाटक के कुल निर्यात 25.87 बिलियन डालर थे जिसमें पेट्रोलियम उत्पाद, लोहा एवं स्टील व आर्गेनिक रसायनों का प्रमुख योगदान है। कर्नाटक ने अपनी मजबूती सिद्ध कर दिखा दिया है। कोविड-19 वैश्विक महामारी के समय में भी राज्य ने सप्लाई श्रृंखला में अपनी वैश्विक प्रतिबद्धताये पूरी की हैं। कर्नाटक में राष्ट्रीय लाकडाउन के समय में भी वैश्विक

श्रृंखलाओं में कोई बाधा नहीं आई है। यह तथ्य ध्यान में रखा जाना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी-भाजपा कर्नाटक की सत्ता में केवल साढ़े तीन साल से है और इस कालखंड में उसका ज्यादातर समय वैशिक महामारी से निपटने में बीता है। इसके बावजूद भाजपा सरकार ने तेज आर्थिक वृद्धि की नीव रखी है। नीति आयोग की तरह कर्नाटक सरकार ने 2022 में कर्नाटक राज्य नीति एवं नियोजन आयोग-केएसपीपीसी का पुनर्गठन कर इसे स्टेट इंस्टीट्यूट फार ट्रांसफारमेशन आफ कर्नाटक-एसआईटीके में बदल दिया जिसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री बासवराज बोम्मई कर रहे थे। इस थिंक टैंक को मुख्यतः विकास संकेतकों में शक्त्रीय असंतुलन दूर करने का काम दिया गया। राज्य सरकार ने पूरे कर्नाटक में उद्योगों और औद्योगिक क्लस्टरों की स्थापना की पहल की। इसके लिए भूमि का पूल बनाया गया तथा शपथपत्र-आधारित निवेश क्लायरेंस व्यवस्था बनाई गई। एसआईटीके अन्य लक्ष्यों में 2030 तक टिकाऊ विकास लक्ष्यों-एसडीजी तथा इंडिया 2047 लक्ष्य प्राप्त करना था। ‘नव कर्नाटक’ के दृष्टिकोण ने इस प्रकार प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के ‘न्यू इंडिया’ लक्ष्य को आगे बढ़ाने का काम किया। राज्य सरकार ने ढाँचात युधार सरल करने का रास्ता दिखाया है। कर्नाटक, 2021 ने ‘ई-

‘सहमति प्लेटफार्म’ का गठन किया। यह सहमति-संचालित व्यवस्था है जिसमें नागरिकों को निजी कंपनियों से अपना डेटा शेयर करने में चयन का पूर्ण नियंत्रण दिया गया है। कर्नाटक सरकार की मुशासन तकनीक ने नागरिकों व खासकर बच्चों तथा वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा मुनिश्चित की है। राज्य सरकार ने निर्भया कंड के अंतर्गत विभिन्न परियोजनाओं पर 667 करोड़ रुपये खर्च किए हैं। इससे 16,000 से अधिक अद्यतन सीसीटीवी कैमरे संवेदनशील स्थानों की जीएसटी मैपिंग के बाद लगाए गए हैं। इसके साथ ही सुरक्षा लाइटें व पैनिक बटन भी लगाए गए हैं। कर्नाटक के राज्य बजट 2023 से बैंगलुरु में 4,100 कैमरे लगाए गए हैं। राज्य सरकार ने आईसीयू वार्डों समेत सभी जिला व तालुक स्तर के अस्पतालों में नागरिकों की सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाए हैं।

कर्नाटक की 68 प्रतिशत से अधिक उत्तमशक्ति कृषि क्षेत्र में कार्यरत है। प्रदेश का कुल 64.50 प्रतिशत क्षेत्र कृषि के अंतर्गत आता है तथा राज्य भारत में बागवानी को सबसे अधिक क्षेत्र देने में पांचवें स्थान पर है। यह सब्जियों के उत्पादन में पांचवें तथा फलों के उत्पादन में तीसरे स्थान पर है। कर्नाटक औषधीय फसलों, ट्रापिकल फलों, ऐरोमैटिक पौधों व मसालों का सबसे बड़ा उत्पादक है।

यह दूसरा सबसे बड़ा दुग्ध-उत्पादक है। कर्नाटक देश में अंगूष्ठों का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। पिछले 42 महीनों में राज्य की भाजपा सरकार ने कर्नाटक को वैश्विक सप्लाई श्रृंखला से जोड़ने का जमीनी काम किया है। कर्नाटक अर्थव्यवस्था की तेज वृद्धि इस तथ्य से देखी जा सकती है कि महाराष्ट्र के बाद कर्नाटक दूसरा सर्वाधिक जीएसटी संग्रह वाला राज्य है। भारत 2047 में अपनी स्वतंत्रता के सौसाल का उत्सव मनाएगा। उसका लक्ष्य उस समय तक कम से कम अर्थव्यवस्था को 30 ट्रिलियन डालर का बनाना है और वह दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनना चाहता है। जब यह समय आएगा तो इस उपलब्धि का असर सबके जीवन पर पड़ेगा तथा जनसंख्या के आम लोग भी समृद्धि का एक स्तर प्राप्त करने में सफल होंगे। लेकिन कुछ बड़े स्वालों के जवाबों की जरूरत है। क्या भारत और खासकर कर्नाटक के लोग इस अवसर का लाभ उठाएंगे या वे कांग्रेस की ‘खेरातों’ वाली प्रतिगामी नीतियों का शिकार बन जाएंगे? कांग्रेस के खेरातों की राजनीति में शामिल होने का कारण क्या यह है कि देश की सबसे पुरानी पार्टी आम आदमी पार्टी-आप की नकल कर रही है? ऐसे में कांग्रेस के सामने कर्नाटक के मतदाताओं के समक्ष यह पेश करने का क्या दृष्टिकोण है कि राज्य 2030 तक 1 ट्रिलियन डालर की अर्थव्यवस्था बनने की उपलब्धि कैसे प्राप्त करेगा?

कर्नाटक के लोग उद्यमी व महत्वाकांक्षी हैं। गुजरात और हरियाणा के अपने समकक्षों की तरह वे पसंद करेंगे कि लाभदायक गतिविधियों से उनकी आमदनी इतनी हो कि वे अपने बिजली बिलों का भुगतान कर सकें। यदि राज्य सरकार उनको 3,000 रुपये महीने देकर खाली बैठने को कहे तो कर्नाटक के नौजवान भावनात्मक रूप से आहत होंगे। कर्नाटक के नौजवान स्टार्टअप शुरू कर रहे हैं। वे उपग्रहों की डिजाइन करने में व्यस्त हैं। वे जानते हैं कि दूरगामी सोच वाली सरकार ही उनको अवसर प्रदान कर सकती है। कर्नाटक एशिया में पनबिजली का लाभ उठाने वाला पहला क्षेत्र था। कर्नाटक भारत का सर्वोच्च हरित ऊर्जा उत्पादक है। कर्नाटक खोज की भूमि है। कर्नाटक शोध एवं विकास का ‘वैश्विक गांव’ है। इसलिए कर्नाटक विकास की राजनीति को अपना आर्शीवाद देगा।

# ईश्वर ही एकमात्र शरणदाता है!

तलाश करने के लिए मार्गदर्शन कर सकते हैं, जो कि ईश्वर है। पिर, जिसे हम आत्रय के रूप में खोजते हैं, वह हमें उपलब्ध नहीं हो सकता है। एक उपयुक्त उदाहरण चिकित्सा पेशे में एक सुपर स्पेशलिस्ट का है। यहां तक कि अगर कोई उनसे संपर्क करने में सक्षम है, तो वह हमेशा हमारी मदद करने में सक्षम नहीं हो सकता है; वास्तव में केवल परमेश्वर ही कर सकता है। कई डॉक्टर ईमानदारी से धोषणा करते हैं: मैं इलाज करता हूँ वह ठीक करता है।

A young boy with a shaved head, wearing a yellow t-shirt and dark shorts, stands at the threshold of a bright doorway. He is looking out into a dark room where a single beam of light illuminates a path on the floor. The doorway is framed by dark walls, creating a strong contrast with the bright light.

सहायता मांगती है तो उसका यौन शोषण किया जाता है। संक्षेप में, दूसरों की शरण लेना खतरे से भरा है। सबसे अच्छी उम्मीद की जा सकती है देना और लेना, और अपने अधिकारों से वंचित न होना, अपमानित होना, आदि। क्योंकि मनुष्य सबसे अच्छा आश्रय नहीं है, भले ही कई बहुत मददार हों; केवल ईश्वर ही वास्तविक आश्रय है। पढ़ते रहिये।

एक संयुक्त परिवार होता है, जिसमें दुर्भाग्य से तीन सदस्यों की अलग-अलग मनोरोग समस्याएं होती हैं। व्यक्ति मिजाज से ग्रस्त होता है। दूसरा बार-बार उदास हो जाता है। और तीसरे के दूसरों से संबंध खराब होते हैं। मूड स्विंग्स वाले व्यक्ति को मदद के लिए मनोविश्लेषक को देखने की जरूरत है डिग्रेशन से ग्रस्त व्यक्ति को मनोचिकित्सक की आवश्यकता होती है। और जो दूसरों के साथ नहीं मिल पाता है, उसे परिवार परामर्शदाता द्वारा मदद की जा सकती है लेकिन तीनों की मदद भगवान कर सकते हैं एक श्लोक में, भगवान निर्देश देते हैं, दुःख और सखे में समझाव का अभ्यास करो: च्व-

स्थित (परेशान नहीं); सुखद और अप्रिय के प्रति टटस्थ; नियमित; और आलोचना और प्रशंसा में तैयार।

पर किसी की निंदा नहीं करता; वह इतना विचारशील और क्षमाशील है। एक प्रश्न पूछा जा सकता है कि पूर्व में सब कुछ बता देने के बाद भी अधिक लोग भगवान की शरण क्यों नहीं लेते। हममें से अधिकांश लोग लालच, वासना और अहंकार से विभिन्न स्तरों तक पीड़ित हैं। हमारे स्वभाव के ये दोष हमें ईश्वर की शरण नहीं लेने देते; वे हमारी बुद्धि पर हावी हो जाते हैं। फिर आश्रय लेने के लिए अपने मन, वचन और शरीर से जो कुछ भी करते हैं उसमें पवित्रता की आवश्यकता होती है। इसे प्राप्त करने के लिए, हमें अनासक्त होने की आवश्यकता है; बहुत सारी ९८% पतस्या करनी चाहिए। एक आधुनिक मनुष्य, अपने ज्ञान पर गर्व करने के बावजूद, आध्यात्मिक सत्यों से घोर अनभिज्ञ है। कोई अन्य किसी भी चीज़ को अस्वीकार करता है या परिणाम के लिए ईश्वर की ओर मुड़ने के लिए बहुत अधीर होता है क्योंकि आध्यात्मिक प्रगति सूक्ष्म और धीमी दोनों होती है। लेकिन उन भाग्यशाली आत्माओं को, जो ऐसा करते हैं, जैसा कि उनके द्वारा अनुभव किया जाता है, भगवान द्वारा सुन्दर रूप से परस्कृत किया जाता है; मेरे पास है।

## आप की बात

## फिल्म का विरोध

हर देश में विपक्ष की भूमिका भी देशहित व सत्य के लिये लड़ने वालों की होती है परन्तु हमारे देश में विपक्ष सच को स्वीकार ही नहीं करता बल्कि सच से भागता भी है। अभी केरल की सत्य घटनाओं पर बनी मूवी दी केरल स्टोरी को देखने के बाद जहां पूरे देश में फ़िल्म बनाने वाले की हिम्मत की तारीफ हो रही है। वहां देश का विपक्ष इस सत्य घटना पर आधारित जनजागरण करने वाली फ़िल्म का विरोध कर रहा है। तमिलनाडु सरकार ने रिलायूज़ के समय से ही इसपर रोक लगा दी थी। अब बंगाल की ममता सरकार ने भी बंगाल में इस पर रोक लगाते हुए कहा है कि ये नफरत फैलाएगी व शांति बनाने के लिये इसको रोकना जरूरी है। कांग्रेस झारखण्ड के विधायक इरफान अंसारी ने कहा है कि समाज से नकारे हुए लोग ही इसको देखने जाएंगे। सपा नेता अबू आज़मी ने फ़िल्म निर्माताओं को ही जेल भेजने की बात कही है। ये काई पहला मौका नहीं है जब भारत का विपक्ष सच को नकार रहा है। इससे पहले कश्मीरी अत्याचार को प्रदर्शित करती दा कश्मीर फाइल का भी इन सभी ने ऐसा ही विरोध किया था। इन सभी दलों के विरोध का एकमात्र कारण है मुश्लिम बोट।

ਮ 1 ਸਾਂ ਵੇਖ ਕੇ ਹੋਰੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਅਤੇ ਮਨੁਸ਼ੀ ਗਲੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।

हंसा आरक्षण से को सोचना चाहिए है।

ना का नतजाह है। जो आरक्षण मात्र खा गया था उसे और तुषीकरण के द्वारा आ रही है। गए हैं कि यदि उसे तो वह आरक्षण बकती। मगर उसे इस अवधि आरक्षण से बंद कर ही देना चाहिए। इटक में मुस्लिम लिंगायतों को की नई कोशिश के लिए आरक्षण

जन्म बातल से बाहर निकलने के बाद वह उर्हे भी निगल सकता है। मणिपुर की घटना का प्रभाव अन्य राज्यों के वातावरण पर न पड़े, अतः सावधानी बरतते हुए सभी राजनीतिक दलों को एकजुट होकर मणिपुर के आंदोलनरत समुदायों को समझाना चाहिए और वहाँ सामाजिक स्थिति बहल की जानी चाहिए। लेकिन विपक्षी अपनी राजनीतिक रोटियां सेंकना चाहते हैं। यह पवृत्ति पूरे देश के लिए विनाशकारी हो सकती है। दुर्मन देश इस आग में धी डालने का प्रयास कर सकते हैं।

दागी नेताओं पर रोक

दागी नेताओं के सियासत में प्रवेश पर ही रोक लगे। वर्तमान में ऐसा कोई दल खोजना मुश्किल है जिसमें दागी नेता न हों, बल्कि हर दल में दागी नेताओं की कमी नहीं है। विडंबना है कि दागी नेताओं को प्रोत्साहित किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट दागी नेताओं के सियासी प्रवेश और दल के गठन आदि पर प्रतिबंध लगाने संबंधी याचिका सुनने को तैयार हुई है, किंतु कानून के अभाव में दागियों को सियासत से बाहर मुश्किल हो रहा है। कुछ दलों के तो हाईकमान में भी दागी पदासीन हैं। चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट दोनों ही दागी नेताओं के सियासत में प्रवेशजारी रहने से नाराज हैं। किंतु सरकार और राजनीतिक दल चुनाव आयोग की संस्तुतियों मानने को तैयार नहीं हैं। कठोर कानून बनाने का अधिकार क्षेत्र नेताओं के पास होने से वे क्या वे अपने खिलाफ सख्त कानून आसानी से पास होने देंगे? जरूरत है प्रबल इच्छाशक्ति वाले ऐसे नेताओं की जो संसद में भी अपनी बात मजबूती से रख सकें। इस दिशा में पहले केन्द्र सरकार की ओर से ही की जानी चाहिए क्योंकि दागी नेताओं पर रोक जरूरी है।











